(c) The amount released to the States of Rajasthan and Madhya Pradesh as grant-in-aid to provide drinking water to problem villages under the Centrally Sponsored Accelerated Rural Water Supply Programme, yearwise, is as under:—

(Rs. in lakhs)

	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81
Rajasthan	252·30	353·27	205·00	359·10
Madhya Pradesh	252·80	290·00	357·15	624·00

एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हैदराबाद

1950. श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज, हैदराबाद के कर्मचारियों ने भारत सरकार से कोई शिकायत की है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस कालेज के कार्यों की कोई जाच की है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) जी, नहीं ।

तथापि, कालेज के कर्मचारी संघ से प्राप्त कुछ अभ्यावेदन सरकार को भेजे गए हैं ।

(ख) अभ्यावेदनों में उठाए गए विषयों के सम्बन्ध में सरकार के विचार कालेज के शासी कोर्ट को, कोर्ट में सरकार के नामजद सदस्य के माध्यम से सूचित कर दिए जाएंगे ।

(ग) भारत सरकार को अभी हाल में हुए ऐसी किसी जांच की जानकारी नहीं है ।

खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग के कार्यकरण में सुधार

1951. श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग के कार्यक्रम का सुधार करने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राशन की दुकानों के माध्यम से अच्छी किस्म के चावल की सप्लाई

1952. श्री दयाराम शाक्य : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में राशन की दुकानों के माध्यम से सप्लाई किये जाने वाले गेहूं